आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

REC Limited | आरईसी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाषः +91 124 444 1300 | वेबसाइटः www.recindia.nic.in
सीआईएनः L40101DL1969GOI005095|जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2) 2025/2168 **दिनांक : 14 फरवरी 2025**

लिस्टिंग विभाग, **नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** **एक्स्चेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,** **बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०००५१**	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग** **बीएसई लिमिटेड** **पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टावर्स** **दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४००००१**
स्क्रिप कोड – आरईसीLTD	**स्क्रिप कोड – 532955**
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Scrip Code -RECLTD	**Scrip Code – 532955**

विषय: 10 फरवरी, 2025 को आयोजित निवेशक सम्मेलन की प्रतिलिपि

महोदय/महोदया,

दिनांक 5 फरवरी, 2025 और 10 फरवरी, 2025 पूर्व सूचना के क्रम में, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसरण में, कृपया 10 फरवरी, 2025 को आयोजित आरईसी लिमिटेड के निवेशक सम्मेलन कॉल (समूह बैठक) का विवरण संलग्न है।

यह आपकी सादर जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

Jyoti Shubhra Amitabh

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न : उपरोक्त अनुसार

“आरईसी लिमिटेड

तृतीय तिमाही वित्त वर्ष ’25 आय कॉन्फ्रेंस कॉल ”

10 फरवरी, 2025

प्रबंधन: **श्री विवेक कुमार देवांगन – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – आरईसी लिमिटेड**

श्री विजय कुमार सिंह – निदेशक (परियोजनाएं) – आरईसी लिमिटेड

श्री हर्ष बवेजा – निदेशक (वित्त) – आरईसी लिमिटेड

श्री मोहन लाल कुमावत – कार्यपालक निदेशक वित्त – आरईसी लिमिटेड

संचालक: **श्री श्रीपाल दोशी – इक्विरस सिक्योरिटीज**

संचालक : देवियों और सज्जनों, नमस्कार, और इक्विरस सिक्योरिटीज द्वारा आयोजित आरईसी लिमिटेड की तीसरी तिमाही वित्त वर्ष '25 कॉन्फ्रेंस कॉल में आपका स्वागत है। एक अनुस्मारक के रूप में, सभी प्रतिभागी पंक्तियाँ केवल सुनने के मोड में होंगी, और प्रस्तुति समाप्त होने के बाद आपके पास प्रश्न पूछने का अवसर होगा। यदि आपको इस कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया अपने टचटोन फोन पर स्टार और फिर शून्य दबाकर ऑपरेटर को संकेत दें। कृपया ध्यान दें कि यह कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड की जा रही है।

अब मैं कॉन्फ्रेंस को इक्विरस सिक्योरिटीज के श्री श्रीपाल दोशी को सौंपता हूं। धन्यवाद, अब आप, सभी को संबोधित करें।

श्रीपाल दोशी : नमस्ते। सभी को सुप्रभात। कॉल को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद, नीरव। हम आप सभी का आरईसी लिमिटेड की आय कोन्फ्रेंस कॉल में स्वागत करते हैं, जिसमें कंपनी के तीसरे तिमाही प्रदर्शन और व्यवसाय अपडेट पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लोग हैं, जिनका प्रतिनिधित्व श्री विवेक कुमार देवांगन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक; श्री विजय कुमार सिंह, निदेशक (परियोजना); श्री हर्ष बावेजा, निदेशक (वित्त); और श्री मोहन लाल कुमावत, कार्यपालक निदेशक वित्त कर रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए, मैं कॉल को सीएमडी महोदय को उनके उद्घाटन भाषण के लिए सौंपता हूँ, जिसके बाद, हम प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया शुरु कर सकते हैं। महोदय, अब आप सभा को संबोधित करें।

विवेक कुमार देवांगन: सभी को सुप्रभात। हमारे तीसरी तिमाही के नतीजे 6 फरवरी को घोषित किए गए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसे देखा होगा। मैं बस कुछ खास बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमारे वितरण में पहले 9 महीनों में काफी वृद्धि हुई है। यह 1,45,647 करोड़ रुपये है। पिछले साल, आपको याद होगा कि कुल वितरण 1,61,462 करोड़ रुपये था। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारा वितरण उस स्तर पर पहुंच गया है और अभी भी लगभग 1.5 महीने बाकी हैं। हमें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में वितरण में काफी वृद्धि होगी।

हमारी ऋण परिसंपत्तियाँ / प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ तीसरी तिमाही में 14% बढ़ी हैं। हालाँकि तीसरी तिमाही में संवितरण अब तक का सबसे अधिक था, जो कि रु. 54,692 करोड़ था, लेकिन कुछ पूर्व भुगतान के कारण, ऋण पुस्तिका में केवल

14% की वृद्धि हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि चौथी तिमाही में, यह ऋण परिसंपत्तियाँ 15% से 17% के बीच बढ़ेंगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हम आने वाले वर्षों में 15% से 17% की वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम होंगे। और इसीलिए हम लक्ष्य बना रहे हैं कि 2030 के अंत तक हमारी प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ लगभग रुपए 10 लाख करोड़ तक बढ़ जाएँगी।

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में हमारा महत्वपूर्ण संवितरण हुआ है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में पहले 9 महीनों में संवितरण में 79% की वृद्धि हुई है। जबकि गैर-विद्युत अवसंरचना और रसद में, इसमें 30% की वृद्धि देखी गई है। कर के बाद लाभ भी 15% बढ़कर 11,477 करोड़ रुपये हो गया है।

अब फंड की लागत पर आते हैं। हम अपने फंड की लागत को लगभग 7.15% तक कम करने में सफल रहे हैं। स्प्रेड 12 आधार अंकों से बढ़कर 2.94% हो गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 12 आधार अंकों से बढ़कर 3.64% हो गया है। नेट वर्थ पर रिटर्न लगभग 21.07% है। डेट-टू-इक्विटी अनुपात 6.38 गुना है और पूंजी पर्याप्तता अनुपात 25.33% है।

हमारा शुद्ध एनपीए 0.74% और सकल एनपीए 1.95% पर आ गया है। यहां, मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि 4 ऑपरेटिंग परिसंपत्तियां हैं जहां हम अच्छे समाधान की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि केएसके महानदी के पहलू में बोली पहले ही पूरी हो चुकी है, जहां हमें मूल राशि के संबंध में 154% की वसूली होने की संभावना है।
लगभग 908 करोड़ रुपये का रिवर्सल होने की संभावना है, और भी रिवर्सल होगा। नासिक में सिन्नर थर्मल परियोजना के संबंध में, मूलधन के संबंध में वसूली लगभग 52.65% है। फिर से, वहाँ भी, हमें लगभग 761 करोड़ रुपये की प्रावधान राशि का रिवर्सल मिलने वाला है। तीसरा, ऑपरेटिंग एसेट हिरणमय परियोजना है जहाँ मूलधन के संबंध में वसूली लगभग 82.75% होने वाली है और प्रावधान का रिवर्सल लगभग 440 करोड़ रुपये होगा। और भद्रेश्वर, प्रावधान का रिवर्सल लगभग 42.59 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

इन सभी ऑपरेटिंग 4 संपत्तियों में, हमारे प्रावधान का उलटफेर लगभग 2,200 करोड़ रुपये होगा। और अधिकांश संपत्तियां, ये ऑपरेटिंग संपत्तियां हैं, समाधान की संभावना है लेकिन एनसीएलटी आदेश में कुछ समय लग सकता है। आदेश चौथी तिमाही में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, अगले वित्तीय वर्ष में भी जा

सकता है। लेकिन दिसंबर 2025 तक, यह सब उलटफेर हो जाएगा। इन कुछ शब्दों के साथ, हमारे पास एक छोटी सी प्रस्तुति है। यदि आप सभी सहमत हैं, तो हम प्रस्तुति देखेंगे।

सुप्रीत पंड्या आरईसी: सुप्रभात, सभी को। हम आपको आरईसी के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दिखाएंगे। प्रस्तुति स्टॉक एक्सचेंजों पर भी अपलोड की गई है। हम आपको प्रस्तुति के माध्यम से ले जाएंगे, जिसमें पिछले 5 दशकों में आरईसी की यात्रा शामिल है, जहां हम 1998 में आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनी से 2022 में महारत्न इकाई तक बढ़े हैं। साथ ही 2024 में, जहां हमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है और 2024 में हमने जेपीवाई 61 बिलियन का अपना पहला येन बॉन्ड जारी किया और 500 मिलियन डॉलर का यूएसडी ग्रीन बॉन्ड जारी किया।

आरईसी की मुख्य ताकत यह है कि यह एक महारत्न कंपनी है और भारतीय बिजली क्षेत्र और बुनियादी ढांचे और रसद क्षेत्र में एक रणनीतिक खिलाड़ी है, जिसके पास विविध परिसंपत्ति आधार और विविध वित्तपोषण स्रोतों तक मजबूत पहुंच है। आरईसी बिजली क्षेत्र के विकास और विकास में एक रणनीतिक स्थान रखता है और अक्षय ऊर्जा खंड और भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी है। आरईसी के पास पर्याप्त प्रावधान कवरेज अनुपात के साथ बहुत ही स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता है। आरईसी के पास मजबूत बुनियादी ढांचे और स्थिर मार्जिन के साथ लाभदायक व्यवसाय है, जिससे मजबूत लाभप्रदता होती है।

रेटिंग के मोर्चे पर, आरईसी को भारत की सभी 4 प्रमुख रेटिंग एजेंसियों से एएए की उच्चतम घरेलू रेटिंग प्राप्त है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हम भारत की सॉवरेन रेटिंग के बराबर हैं और मूडीज से बीएए3 रेटिंग, फिच से बीबीबी- रेटिंग और जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बीबीबी+ रेटिंग प्राप्त है। हम भारत सरकार के प्रमुख बिजली क्षेत्र के कार्यक्रमों जैसे आरडीएसएस, सौभाग्य, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम आदि के लिए नोडल एजेंसी हैं। हमारे पास क्षेत्र की विशेषज्ञता वाली एक अनुभवी और प्रबंधन टीम है।

आरईसी उन कुछ प्रतिष्ठित भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है, जिन्हें महारत्न का दर्जा प्राप्त है, जो भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सर्वोच्च रैंक है। हम केवल उन 14 सार्वजनिक उपक्रमों में से हैं, जिन्हें यह दर्जा दिया गया है। यह महारत्न का दर्जा हमें अधिक परिचालन और

वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है। यह हमें भारत और विदेशों में संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियों और एम एवं ए गतिविधियों को शामिल करके रणनीतिक निवेश करने की भी अनुमति देता है। इससे हमें विकास में तेजी लाने और बिजली क्षेत्र के लिए सरकार के दृष्टिकोण को समर्थन देने में भी मदद मिलती है।

आरईसी ने गैर-बिजली अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 33% तक ऋण देने के अधिदेश के साथ ऋण पोर्टफोलियो में भी विविधता लाई है, जहाँ हम मेट्रो, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, तेल रिफाइनरी, सड़क और राजमार्ग, आईटी इंफ्रा, फाइबर ऑप्टिक्स, स्टील इंफ्रा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी वित्त पोषित कर रहे हैं। हम आपको शेयरधारकों के दृष्टिकोण के बारे में आगे ले जाएँगे। 31 दिसंबर 2024 तक, हम 52.63% पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमुख रूप से रखे गए हैं। 2008 में आईपीओ के बाद से एफपीआई और एफआईआई ने आरईसी में 20% से अधिक की हिस्सेदारी जारी रखी है और अभी भी आरईसी में 21.74% हिस्सेदारी रखते हैं। बीमा कंपनियों के पास 4% हिस्सेदारी है। व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई के पास 10.58% हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड और एआईएफ के पास लगभग 9% हिस्सेदारी है। कॉर्पोरेट बैंक एफआई के पास आरईसी इक्विटी का 1.7% और अन्य के पास 0.23% हिस्सेदारी है। आरईसी के सबसे बड़े शेयरधारकों में पावर फाइनेंस के अलावा सिंगापुर सरकार, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट ट्रस्टी, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन का एनपीएस ट्रस्ट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई क्वांट फंड, वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड और सामान्य बीमा कंपनी टाटा एआईजी शामिल हैं।

लाभांश के मोर्चे पर, हमने तीसरी तिमाही वित्तीय वर्ष '25 के लिए 4.30 रुपए प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जो पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए क्रमशः रुपए 3.5 और रुपए 4 प्रति शेयर के पहले और दूसरे अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। इस तीसरे अंतरिम लाभांश के बाद, आरईसी द्वारा घोषित कुल अंतरिम लाभांश रुपए 10 के अंकित मूल्य पर रुपए 11.8 प्रति शेयर है।

हमें आपको यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आरईसी को बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के अलावा वित्तीय सेवा क्षेत्र के तहत आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की ओर से गोल्ड शील्ड से सम्मानित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार। यह

कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जोखिम शमन और कई अन्य क्षेत्रों में हमें मिलने वाले विभिन्न पुरस्कारों के अतिरिक्त है।

आइये तिमाही और समाप्त 9 महीनों के लिए परिचालन प्रदर्शन पर आते हैं। वित्त वर्ष 2025 के 9 महीनों के दौरान, आरईसी ने 2,71,814 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 79,135 करोड़ रुपये की नवीकरणीय परियोजनाएं शामिल हैं। मंजूरी का विवरण प्रस्तुति के स्लाइड #13 पर उपलब्ध है।

दिसंबर 2025 को समाप्त 9 महीनों के दौरान, आरईसी ने 1,45,647 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जो आरईसी द्वारा अब तक का सबसे अधिक तिमाही और 9 महीने का संवितरण है। यह वित्त वर्ष '24 के 9 महीनों की तुलना में वित्त वर्ष '25 के 9 महीनों में 19% की वृद्धि दर्शाता है। आरईसी के प्रारंभिक मार्गदर्शन के अनुसार, वित्त वर्ष '25 के 9 महीनों के दौरान वित्त वर्ष 2024 के 9 महीनों की तुलना में नवीकरणीय संवितरण में 79% की वृद्धि हुई है।

31 दिसंबर 2024 तक बकाया ऋण पुस्तिका 5,65,621 करोड़ रुपये है, जो साल-दर-साल 14% की वृद्धि दर्शाती है। नवीनीकरण पुस्तिका में भी पिछले वर्ष की तुलना में 58% की अच्छी वृद्धि देखी गई है और 31 दिसंबर 2024 तक यह 52,394 करोड़ रुपये है। हम भारत के सभी राज्यों में अखिल भारतीय उपस्थिति बनाए हुए हैं और राज्य क्षेत्र का बकाया 4,98,444 करोड़ रुपये के करीब है और निजी क्षेत्र की पुस्तिका 31 दिसंबर 2024 तक लगभग 67,177 करोड़ रुपये है।

आरईसी के हमारे शीर्ष 10 प्रमुख उधारकर्ताओं में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड शामिल हैं, जिसका बकाया 39,670 करोड़ रुपये है; महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड 27,023 करोड़ रुपये; तमिलनाडु पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 22,249 करोड़ रुपये, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना निगम लिमिटेड 17,911 करोड़ रुपये; उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 17,732 करोड़ रुपये; तेलंगाना राज्य बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड 17,242 करोड़ रुपये; आंध्र प्रदेश दक्षिणी बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड 17,233 करोड़ रुपये; जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 15,406 करोड़ रुपये; तेलंगाना राज्य दक्षिणी बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड 15,042 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड 14,813 करोड़ रुपये। आरईसी के पास एक अच्छी तरह से विविध परिसंपत्ति पोर्टफोलियो है जिसमें शीर्ष 10 उधारकर्ताओं के पास बकाया ऋणों का लगभग 36% हिस्सा है शीर्ष 10

उधारकर्ताओं में से किसी के पास कुल ऋण पुस्तिका का 8% से अधिक हिस्सा नहीं है, तथा शीर्ष 10 खातों में कभी भी कोई एनपीए नहीं रहा है।

आरईसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता की बात करें तो दिसंबर 2024 तक परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और सकल एनपीए घटकर 1.95% और शुद्ध एनपीए घटकर 0.74% रह गया है, जिसका मुख्य कारण 3 परिसंपत्तियों का समाधान है, जो लैंको अमरकंटक, नागाई पावर और लिंक्स हैं, जिनका कुल बकाया लगभग 2,778 करोड़ रुपये है। इन एनपीए के समाधान के परिणामस्वरूप, 31 दिसंबर 2024 तक प्रावधान कवरेज अनुपात 61.88% है। स्लाइड नंबर 20 पर प्रस्तुति में श्रेणी-वार ईसीएल प्रावधान भी उपलब्ध है। और फिर से पुष्टि करने के लिए, राज्य क्षेत्र में कोई एनपीए नहीं है। हमारे पास एनपीए पर लगभग 62% का प्रावधान है। और इसके अलावा, हमारे पास मानक परिसंपत्तियों पर 0.73% का प्रावधान भी है। इन प्रावधानों के अतिरिक्त, हमारे पास आरबीआई अधिनियम की धारा 45आईसी के तहत वैधानिक रिजर्व के रूप में और आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(वीआईआईए) के तहत खराब और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व भी उपलब्ध है, जिनकी राशि क्रमशः 13,134 करोड़ रुपये और 1,320 करोड़ रुपये है।

हमारे मौजूदा एनपीए समाधान के विभिन्न चरणों में हैं। एनसीएलटी के अंतर्गत लगभग 13 परियोजनाएं हैं, जिनमें लगभग 9,543 करोड़ रुपये बकाया हैं और 68% प्रावधान है। जबकि एनसीएलटी के बाहर भी एक परियोजना चल रही है, जिसमें 1,503 करोड़ रुपये बकाया हैं और 50% प्रावधान है।

आरईसी की उधारी प्रोफ़ाइल पर, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, हम मूडीज़, फ़िच और जापान क्रेडिट एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग को जारी रखते हैं, और घरेलू रेटिंग एएए है, जो सभी 4 प्रमुख रेटिंग एजेंसियों द्वारा उच्चतम है। आरईसी के सतत ऋण को भी केयर और क्रिसिल द्वारा उच्चतम एएए रेटिंग दी गई है।

31 दिसंबर 2024 तक आरईसी की बकाया उधारी बढ़कर 4,89,595 करोड़ रुपये हो गई है, जो साल-दर-साल 13% की वृद्धि है। हमारे पास व्यापार वृद्धि को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्रोतों के मिश्रण के साथ वित्तपोषण के कई स्रोतों तक पहुंच है। हम उन केवल 4 कंपनियों में से एक हैं जिन्हें कम लागत वाले पूंजीगत लाभ कर छूट बांड जुटाने की अनुमति है।

वित्त वर्ष 2025 के 9 महीनों के दौरान, हमने 1,15,020 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सभी क्षेत्रों से जुटाई गई है।

9 महीनों के वित्तीय पहलुओं पर कुछ संक्षिप्त प्रकाश डालना है। हमने 9 महीनों में अब तक का सबसे अधिक 11,477 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ दर्ज किया है। कुल आय 40,805 करोड़ रुपये रही, जो साल-दर-साल 18% की वृद्धि है। शुद्ध ब्याज आय 14,191 करोड़ रुपये रही, जो साल-दर-साल 24% की वृद्धि है। 9 महीनों के लिए शुद्ध लाभ 11,477 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 15% की वृद्धि है। लोन बुक भी 5.66 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो 14% की वृद्धि है। एसेट क्वालिटी 0.82% से सुधरकर 0.74% हो गई है। आरईसी की नेटवर्थ 76,502 करोड़ रुपये रही, जो साल-दर-साल 18% की वृद्धि है। आरईसी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 25.33% पर है, जबकि टियर 1 पूंजी 22.95% है। यह आरबीआई द्वारा 15% की आवश्यकता के विरुद्ध है। इसलिए आरईसी पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है। आरईसी के प्रमुख अनुपातों पर, 9 महीनों के लिए ऋण परिसंपत्तियों पर उपज पिछले वर्ष के 9.98% से बढ़कर 10.09% हो गई है। लागत पिछले वर्ष के 7.16% से 7.15% पर स्थिर रही है। परिणामस्वरूप, ब्याज प्रसार 2.94% तक सुधर गया है और शुद्ध ब्याज मार्जिन भी 3.64% तक सुधर गया है। नेटवर्थ पर रिटर्न 21.07% पर प्रभावशाली बना हुआ है। ब्याज कवरेज अनुपात 1.57x और ऋण इक्विटी अनुपात 6.38x पर काफी पर्याप्त है। प्रस्तुति के स्लाइड #29 पर लाभप्रदता कथन भी दिया गया है।

तीसरी तिमाही में हमने 4,029 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष के 3,269 करोड़ रुपये से 23% अधिक है। 9 महीनों में हमने 11,477 करोड़ रुपये का कुल लाभ दर्ज किया है, जो 15% की वृद्धि है। यह पिछले वर्ष के 14,019 करोड़ रुपये के लाभ के अनुरूप है। प्रस्तुति की स्लाइड #30 पर बैलेंस शीट की स्थिति भी दी गई है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, नेटवर्थ बढ़कर 76,502 करोड़ रुपये हो गई है, जो 18% की वृद्धि है।

इस वर्ष से, हमने आरईसी लिमिटेड में ईएसजी पर स्लाइड भी दी हैं। ईएसजी के मोर्चे पर आरईसी क्या कर रहा है, इसका विवरण स्लाइड संख्या 31 से आगे की प्रस्तुति में दिया गया है। आपको ईएसजी के मोर्चे पर बहुत ही संक्षिप्त विवरण देने के लिए।

जनवरी 2023 में बोर्ड द्वारा आरईसी ईएसजी नीति को मंजूरी दी गई थी। जून 2023 में तिमाही अनुपालन के लिए ईएसजी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उसके बाद, फरवरी 2024 में, नई ईएसजी-संबंधित नीतियों को पेश किया गया और अधिक मानवाधिकार और कल्याण प्रशिक्षण आयोजित किए गए। अप्रैल 2024 में, सभी आरईसी कार्यालयों के जीएचजी उत्सर्जन का मूल्यांकन पूरा हो गया। आरईसी ने अगस्त 2024 में जीआरआई प्रारूप के संदर्भ में अपनी पहली ईएसजी रिपोर्ट प्रकाशित की है। और अक्टूबर 2024 में, आरईसी ने स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन में शुद्ध शून्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आरईसी द्वारा की जा रही आरईसी - संबंधित गतिविधियों का विवरण और आने वाले वर्षों के लिए हमने क्या लक्ष्य रखा है, यह भी प्रस्तुति में दिया गया है। इसके साथ, हम प्रश्न-उत्तर दौर के लिए खुले हैं और प्रबंधन निवेशकों से प्रश्न लेने में प्रसन्न है।

मॉडरेटर: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पहला सवाल सीएलएसए इंडिया की श्रेया शिवानी की ओर से है।

श्रेया शिवानी: उन्नति के लिए बधाई। महोदय, मेरे पास 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि मैं प्रीपेमेंट बिट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझना चाहती थी। तो पुनर्भुगतान दर, जो मैं देख रही थी, उसमें हमारे खंड के लिए वितरण क्षेत्र में पिछले कुछ तिमाहियों से वृद्धि बनी हुई है। मैं मान रहा हूँ कि यह आरबीपीएफ योजना के कारण है।

यदि आप हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि क्या वह योजना वितरण खंड में देखी गई उच्च पुनर्भुगतान दर में योगदान दे रही है। साथ ही, इस तिमाही में, ऐसा लगता है कि नवीकरणीय सहित जेनको बुक में पुनर्भुगतान दर भी बढ़ी है। तो क्या पूर्व भुगतान नवीकरणीय जेनको बुक से आया है? या क्या यह केवल उच्च डिस्कॉम पूर्व भुगतान पुनर्भुगतान है जो हम देख रहे हैं जिसने इस तिमाही में हमारी वृद्धि को धीमा कर दिया है? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा, हमारा झारखंड में अदानी प्लांट से संपर्क है, मुझे विश्वास है, जो पड़ोसी देश को बिजली प्रदान करता है। महोदय, क्या हमें वहां कोई चिंता है? क्या हमने उस संपत्ति पर कोई प्रावधान बढ़ाया है? या कोई ऐसा रंग जो आप हमें दे सकते हैं जो उपयोगी होगा?

विवेक कुमार देवांगन: शिवानी, बहुत ही उचित प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। आपने सही कहा कि हमने वितरण कंपनियों को रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा दी है। रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा के संबंध में बहुत सारे पुनर्भुगतान हुए हैं। और उत्पादन के संबंध में, कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में कुछ पूर्व भुगतान हुए हैं क्योंकि आप नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की प्रकृति जानते हैं। 2 से 3 साल में चालू होने के बाद, प्रमोटर अपनी इक्विटी बेचना चाहता है और फिर उसका मुद्रीकरण करना चाहता है और फिर नई परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ना चाहता है।

तो वास्तव में यही चलन है। आप इन सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में देखेंगे कि इस परियोजना को बेचने की प्रवृत्ति है। और झारखंड में अडानी पावर प्लांट के संबंध में, भारत सरकार ने झारखंड में अडानी पावर जेनरेशन कंपनी को अनुमति दी है। यदि बांग्लादेश से कोई उठाव नहीं होता है, तो वे घरेलू बाजार में बेच सकते हैं। हालांकि, पुनर्भुगतान समय पर हो रहा है और हमें अदानी पावर प्लांट से पुनर्भुगतान के संबंध में कोई चिंता नहीं दिखती। मैं निदेशक वित्त से इस पुनर्भुगतान मुद्दे पर पुष्टि करने का अनुरोध करूंगा।

हर्ष बवेजा: दरअसल, आप जानते होंगे कि हमारा औसत पुनर्भुगतान लगभग 9,000 करोड़ रुपये प्रति माह है। इसलिए यह बिल्कुल सही दिशा में है। तिमाही के दौरान ही, हमें 27,000 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान मिला है, जो एक नियमित पुनर्भुगतान है। और 5,600 करोड़ रुपये आरबीपीएफ के लिए है, जो फिर से व्यवसाय के नियमित क्रम में है। यह राशि उनके द्वारा भेजी जाती है और फिर, हम उन्हें वितरित करते हैं। इसलिए यह हमारी ऋण पुस्तिका को प्रभावित नहीं करता है।

महत्वपूर्ण बात पूर्व भुगतान के बारे में थी, जो हमें एसीएमई से मिला है। यह लगभग 2,000 करोड़ रुपये है, जो इस तथ्य के कारण है कि कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के लिए कदम उठाया है। इसलिए उनकी आय में से, उनके लिए हमें पूर्व भुगतान करना अनिवार्य था। इस प्रकार यह पूर्व भुगतान हर महीने प्राप्त होने वाले नियमित पुनर्भुगतान के अतिरिक्त है।

श्रेया शिवानी: समझ गई, सर। यह बहुत उपयोगी है। सर, संवितरण प्रवृत्ति पर अंतिम अनुवर्ती प्रश्न। पहली बार आपने अपने पीपीटी में आरडीएसएस संवितरण डाला है। यह उस स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम की ओर है। यह बहुत छोटी संख्या है, लेकिन क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह खंड अगली तिमाही से बढ़ना शुरू हो जाएगा?

विवेक कुमार देवांगन: बहुत-बहुत धन्यवाद श्रेया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत 2 घटक हैं। एक है घाटा कम करने का काम और दूसरा है प्रीपेड स्मार्ट मीटर। हमने जो पूंजीगत व्यय ऋण स्वीकृत किया है, वह घाटा कम करने के काम के लिए है। और शुरुआत में वितरण कंपनियों ने भारत सरकार के अनुदान का 20% तक उपयोग किया है। अब काम में तेजी आ रही है। और हमें उम्मीद है कि अगले साल और उसके बाद के साल में आरडीएसएस घाटा कम करने के काम के लिए पर्याप्त धन का वितरण होगा।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में, यह एएमआईएसपी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जा रहा है, वे निजी खिलाड़ी जिन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बोली जीती है। वे टॉटएक्स मोड में मीटर लगा रहे हैं। इसलिए वे हमसे ऋण मांग रहे हैं, और हमने इन प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऑपरेटरों को लगभग 7,000 करोड़ रुपये का ऋण पहले ही स्वीकृत कर दिया है। अगले 2 वर्षों में इसमें भी तेजी आने की संभावना है। मैं निदेशक परियोजनाओं से अनुरोध करूंगा कि वे इसे और अधिक रंग दें।

विजय कुमार सिंह: मुझे लगता है कि आरडीएसएस में हमने 2 तरह की फंडिंग की है। एक को काउंटरपार्ट फंडिंग कहा जाता है, जो कि 40% बची हुई पूंजीगत व्यय राशि है। 60%, आप जानते हैं कि यह भारत सरकार के अनुदान से आ रहा है और 40%, कुछ छूट का लाभ अब उठाया जा चुका है। तो हमने वह फंडिंग की है। हमने एक फंडिंग भी की है जिसे हम अंतरिम फंडिंग कहते हैं, मुझे लगता है कि डिस्कॉम को ये अनुदान थोड़ा देर से मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने पूंजीगत व्यय कार्यक्रम को जारी रखना होगा। इसलिए हमने उन्हें 60% तक भी इस शर्त के साथ समर्थन दिया है कि जब भी उन्हें अनुदान मिले, वे उसे चुका दें।

ये 2 तरह की फंडिंग आरडीएसएस के अंतर्गत है, जैसा कि सीएमडी सर ने कहा कि हम एएमआईएसपी का भी समर्थन कर रहे हैं। हमने जेमस्टार के लिए बड़ी परियोजनाएं की हैं, लगभग 4,500 करोड़ रुपये। हमने इंटेलीस्मार्ट भी किया है और हमारे ऋण पर अन्य प्रस्ताव भी हैं, जो वर्तमान में मूल्यांकन के अधीन हैं। तो निश्चित रूप से, मेरा मतलब है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, वास्तव में, हम पहले भी यह कह रहे थे कि इस वर्ष से, यह विशेष खंड आगे बढ़ेगा। हम आगे भी संवितरण होते देखेंगे।

अनुवाद जारी है।